Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP,
Ludhiana, Shimla,
Bihar, Jammu, Jaipur
Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Tue - 23 Jun - 2026 | Year - 01 | Issue - 78 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

मास्टाइटिस की रोकथाम से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को किया जागरूक

मोहाली, 23 जून: पशुपालन विभाग पंजाब द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गांव चूड़ियाला स्थित गुरुद्वारा साहिब में "मास्टाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के माध्यम से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन" विषय पर किसान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर पशुपालन विभाग पंजाब के निदेशक के दिशा-निर्देशों तथा जिला एस.ए.एस. नगर के उपनिदेशक डॉ. अवतार सिंह और एस.वी.यू. डॉ. सविता कांसल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

शिविर में बड़ी संख्या में पशुपालक किसानों ने भाग लिया और पशुओं में होने वाली मास्टाइटिस बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अब्दुल माजिद और डॉ. मनदीप कौर ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि मास्टाइटिस दुग्ध देने वाले पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जो पशुओं के थनों को प्रभावित करती है। इस बीमारी के कारण दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी आती है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

विशेषज्ञों ने किसानों को मास्टाइटिस के प्रमुख कारणों, प्रारंभिक लक्षणों, उपचार की विधियों तथा प्रभावी रोकथाम उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूध दुहने से पहले और बाद में थनों की उचित सफाई, पशुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना तथा बीमारी की समय पर पहचान करना इसके नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाकर इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान वेटरनरी इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह और जगजीवन सिंह ने भी किसानों को पशुओं की देखभाल, पोषण प्रबंधन तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में किसानों के साथ खुला संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें पशुपालकों ने दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। विभागीय अधिकारियों ने उनके सभी प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किया तथा व्यावहारिक सुझाव प्रदान किए।

अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के मानकों को अपनाएं, पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं तथा किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि इससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित दूध उपलब्ध हो सकेगा।

कार्यक्रम के अंत में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एवं गांववासियों का सफल आयोजन के लिए धन्यवाद किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया।

7 असफल IVF साइकिल्स के बाद मां बनीं संभावना सेठ, साझा किया संघर्ष और हौसले

चंडीगढ़: अभिनेत्री और यूट्यूबर संभावना सेठ ने शो "तुम हो ना – घर की सुपरस्टार" में अपनी मातृत्व यात्रा का भावुक अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि शादी के 10 वर्षों के दौरान मां बनने का सफर आसान नहीं रहा। शादी से पहले एम्ब्रियो फ्रीज़ कराने के बावजूद उन्हें लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। संभावना ने खुलासा किया कि उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि सात IVF साइकिल्स करवाईं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

उन्होंने कहा कि मां बनने की चाहत में एक महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कुछ सहना पड़ता है। संभावना ने अपने पति अविनाश की सराहना करते हुए बताया कि कठिन समय में उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। अविनाश ने उनसे कहा था कि उन्हें बच्चे से ज्यादा उनकी खुशी की चिंता है।

संभावना ने बताया कि बच्चों के प्रति अपने प्रेम और मातृत्व की इच्छा के कारण उन्होंने हार नहीं मानी।

मैक्स अस्पताल और ब्रह्माकुमारीज ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

मोहाली: मैक्स अस्पताल मोहाली और ब्रह्माकुमारीज, एयरो सिटी मोहाली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 272 लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में योगासन, प्राणायाम, ध्यान तथा समग्र स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवनशैली पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर मैक्स अस्पताल की मेडिकल ऑन्कोलॉजी सलाहकार डॉ. आकांक्षा ने कहा कि नियमित योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, तनाव कम करता है तथा जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भगवंत मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई, मोगा नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस

चंडीगढ़/मोगा, 23 जून: पंजाब सरकार ने राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मोगा नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा मोगा शहर के औचक निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे "मिशन क्लीन पंजाब" के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सुबह शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर खुले में पड़े कूड़े के ढेर और असंतोषजनक सफाई व्यवस्था देखने को मिली, जो सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छता मानकों के विपरीत पाई गई। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही या अनदेखी के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और किसी भी अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बेहतर जीवन स्तर और स्वच्छ शहरों के हकदार हैं तथा इस दिशा में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि "मिशन क्लीन पंजाब" केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम आयुक्तों और कार्यकारी अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फील्ड निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शहरों को 10 किलोमीटर के जोनों में विभाजित किया गया है, जिनकी निगरानी नामित अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

30 जून तक पंजाब होगा 'ओपन मैनहोल फ्री', लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़, 22 जून : पंजाब सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के सभी शहरों को 30 जून 2026 तक 'ओपन मैनहोल-फ्री' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्थानीय निकाय मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने सभी नगर निगम कमिश्नरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (शहरी विकास) को निर्देश जारी करते हुए तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'मिशन क्लीन पंजाब' के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर किए गए सुरक्षा ऑडिट के दौरान मानसून सीजन से पहले विभिन्न शहरों में कुल 1451 खुले मैनहोल चिन्हित किए गए थे, जो आम लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। इनमें से 1000 से अधिक मैनहोलों को पहले ही सुरक्षित रूप से बंद किया जा चुका है, जबकि शेष मैनहोलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कवर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में खुले मैनहोल हादसों का बड़ा कारण बनते हैं और कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि खुले मैनहोल विशेष रूप से बारिश के दिनों में 'मौत के कुएं' साबित हो सकते हैं। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने इस अभियान के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभियान की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग ने एक ए.आई.-एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की है, जिसके माध्यम से खुले मैनहोलों को बंद करने की प्रक्रिया की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा सभी सिविल अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फील्ड निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जा सके।

सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में विशेष वार रूम भी स्थापित किए हैं, जहां तैनात कर्मचारी 24 घंटे जलभराव, सीवर जाम और मानसून से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेंगे। स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि लक्ष्य पूरा करने के लिए अब केवल आठ दिन शेष हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार का यह अभियान राज्य के शहरों को सुरक्षित, स्वच्छ और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे मानसून के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

SQUARENET
Innovation & Excellence

Zoho Mail
Google Workspace
Microsoft 365

Microsoft Solutions Partner | Google Cloud Partner | aws partner network

Are you looking for a reliable
EMAIL SERVICE PROVIDER?
Choose the best suitable plan for your business from SquareNet

Secure & Reliable | Professional Email | Cloud Integration | 24/7 Expert Support | Scalable for Every Business

Advertisement

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com
mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

दिव्यांगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 125 करोड़ रुपये से अधिक जारी, सहायता में देरी बर्दाश्त नहीं होगी : डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 23 जून: पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए दी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जरूरतमंद और दिव्यांग व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचे। उन्होंने बताया कि मई 2026 तक राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में 125 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। यह उपलब्धि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उनकी भलाई के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी इस जनकल्याणकारी योजना को प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए 498 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ वर्तमान में राज्य के 2.83 लाख से अधिक दिव्यांग लाभार्थियों को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहें और सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

उन्होंने योजना की पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि वे दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम है। साथ ही आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए तथा वह अपनी आजीविका अर्जित करने में असमर्थ हो। ऐसे पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा नियमित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना|

चार कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को जायज मांगों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए

मोहाली, 23 जून: पशुपालन विभाग पंजाब द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गांव चूड़ियाला स्थित गुरुद्वारा साहिब में "मास्टाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के माध्यम से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन" विषय पर किसान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर पशुपालन विभाग पंजाब के निदेशक के दिशा-निर्देशों तथा जिला एस.ए.एस. नगर के उपनिदेशक डॉ. अवतार सिंह और एस.वी.यू. डॉ. सविता कांसल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

शिविर में बड़ी संख्या में पशुपालक किसानों ने भाग लिया और पशुओं में होने वाली मास्टाइटिस बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अब्दुल माजिद और डॉ. मनदीप कौर ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि मास्टाइटिस दुग्ध देने वाले पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जो पशुओं के थनों को प्रभावित करती है। इस बीमारी के कारण दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी आती है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

विशेषज्ञों ने किसानों को मास्टाइटिस के प्रमुख कारणों, प्रारंभिक लक्षणों, उपचार की विधियों तथा प्रभावी रोकथाम उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूध दुहने से पहले और बाद में थनों की उचित सफाई, पशुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना तथा बीमारी की समय पर पहचान करना इसके नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाकर इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान वेटरनरी इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह और जगजीवन सिंह ने भी किसानों को पशुओं की देखभाल, पोषण प्रबंधन तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में किसानों के साथ खुला संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें पशुपालकों ने दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। विभागीय अधिकारियों ने उनके सभी प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किया तथा व्यावहारिक सुझाव प्रदान किए।

अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के मानकों को अपनाएं, पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं तथा किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि इससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित दूध उपलब्ध हो सकेगा।

कार्यक्रम के अंत में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एवं गांववासियों का सफल आयोजन के लिए धन्यवाद किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया।

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई: रिश्वत लेने के आरोप में इंस्पेक्टर और जूनियर ऑडिटर गिरफ्तार

चंडीगढ़, 23 जून 2026: पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दो अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोगपुर (जिला जालंधर) में तैनात इंस्पेक्टर रजनीश रामपाल तथा जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जालंधर कार्यालय में कार्यरत जूनियर ऑडिटर मानव भनोट शामिल हैं।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर प्राप्त एक शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत चीमा मंडी, तहसील सुनाम, जिला संगरूर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए आवंटित धान के भंडारण कार्य को पूरा करने के बदले संबंधित अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी।

जांच के दौरान विजिलेंस ब्यूरो ने पाया कि इंस्पेक्टर रजनीश रामपाल ने शिकायतकर्ता के शैलर में धान के भंडारण कार्य को पूरा करने के लिए पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये रिश्वत ली थी। इसके बाद उसने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोगपुर में तैनात एएफएसओ गुरविंदर सिंह के नाम पर दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये और प्राप्त किए। इस प्रकार उसने कुल 70,000 रुपये की रिश्वत ली।

इसी तरह जांच में यह भी सामने आया कि जूनियर ऑडिटर मानव भनोट ने अपने लिए तथा जिला नियंत्रक नरेंद्र सिंह के नाम पर शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये रिश्वत ली थी। यह राशि भी शैलर में धान के भंडारण से संबंधित कार्य को पूरा करवाने के बदले मांगी और प्राप्त की गई थी।

विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा तैयार की गई वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसमें रिश्वत लेने संबंधी आरोपों की पुष्टि हुई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो ने बताया कि जांच के दौरान इस मामले में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जाएगी।

चार कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को जायज मांगों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए

चंडीगढ़, 23 जून 2026: पंजाब सरकार राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे हेतु गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एवं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज चार कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कर उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा की।

अपने कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा सौंपे गए मांग पत्रों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनकी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।

हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले से विचाराधीन मामलों की प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी से कर्मचारियों में असंतोष पैदा होता है, इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की जायज मांगों के निपटारे में किसी भी प्रकार की गैर-जरूरी प्रक्रिया या विलंब से बचा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रस्तावों को व्यवस्थित रूप से तैयार कर समयबद्ध तरीके से कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच पारदर्शी, सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नियमित संवाद और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके।

बैठकों में कोविड-19 मेडिकल एवं पैरामेडिकल वॉलंटियर यूनियन, जल सप्लाई एवं सैनिटेशन सोशल इम्प्लाइज यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे-मील कार्यालय कर्मचारी यूनियन तथा एसोसिएट प्री-प्राइमरी अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर यूनियनों के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह, राजिंदर सिंह संधा, जगमोहन सिंह, राजविंदर सिंह, नवजोत सिंह, अमनदीप कंबोज, गुरप्रीत सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण, लाभकारी और पारदर्शी संबंध बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है तथा उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हर संभव

1050 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत : हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़/श्री मुक्तसर साहिब, 23 जून: पंजाब सरकार के 'ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026' कार्यक्रम के तहत श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित समारोह में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले 1050 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा समाज की हर समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही युवाओं को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्कूलों की वार्षिक फीस वृद्धि 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। पिछले तीन वर्षों में अनुचित फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभिभावकों से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस करवाई जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और आज राज्य देश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की पीजीआई 2.0 रैंकिंग में पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में पहला स्थान मिला है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। इस अवसर पर मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ खुला संवाद किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था की मजबूती पर निर्भर करती है।

पंजाब में सरकारी नौकरियों का नया दौर: 68,268 युवाओं को मिला रोजगार, विदेश गए युवा भी लौट रहे हैं – मुख्यमंत्री

बठिंडा, 23 जून 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य में पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रणाली लागू होने के बाद पंजाब सरकारी नौकरियों के लिए देश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पहले रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले अनेक युवा अब वापस पंजाब लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य में योग्यता के आधार पर रोजगार मिलने का विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में चयनित 665 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 68,268 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी नौकरियों में रिश्वत, सिफारिश और राजनीतिक दबाव का बोलबाला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब केवल योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है कि अब तक किसी भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे विदेशों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को पंजाब लौटने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को पंजाब के विकास का भागीदार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली एक युवती को तीन अलग-अलग नौकरियों में

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक बदलाव ला रही है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा सुधारों के कारण पंजाब आज प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक शिक्षण तकनीकों और शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण ने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने इस क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद उन्हें उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी। इससे पारिवारिक जीवन और कार्य के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग जनकल्याण के लिए कर रही है। मुफ्त बिजली, बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और शिक्षा क्षेत्र में निवेश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है और कई टोल प्लाजा बंद कर लोगों को आर्थिक राहत दी गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 30 लाख से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जा चुके

herbegy™
Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.